मंथन

खनिज भंडार से आत्मनिर्भरता

अनिल अग्रवाल
अध्यक्ष, वेदांता समूह

भारत में प्राकृति संसाधनों की प्रचुरता है। परंतु उसकी खोज का महंगा एवं जटिल होना इसकी राह में रोड़ा है, जिसे दूर करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को समय रहते प्राप्त किया जा सकता है

देश को वर्ष 2047 तक "विकसित भारत" बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए देश को आत्मनिर्भरता का रास्ता ही अपनाना होगा, क्योंकि कोई भी देश आयातक बनकर विकसित नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस बात से परिचित हैं और उनका आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशी का आह्वान सही समय पर है। देश के आयात बिल में कच्चे तेल, सोना, तांबा और बाक्साइट की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है। इलेक्ट्रानिक्स सामान भी आयात में 15 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। सरकार ने इलेक्ट्रानिक्स के आयात को कम करने के लिए घरेलू उत्पादन पर जोर दिया है। आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के घरेलू उत्पादन को भी प्राथमिक रूप से शामिल किया जाए।

सौभाग्य से देश की धरती खनिजों से भरी पड़ी है। प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से भारत की भूगौलिक स्थिति आस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बराबर है। लाखों साल पहले ये सभी भौगोलिक क्षेत्र एक ही भूभाग का हिस्सा थे, और भारत समेत इन सभी में खनिजों और हाइड्रोकार्बन के बड़े-बड़े भंडार हैं। अंतर केवल इतना है कि अन्य भौगोलिक क्षेत्रों यानी आस्ट्रेलिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका ने अपने खनिज भंडारों को खोजा और उनका खनन किया। लेकिन हम अभी इसमें पिछड़े हुए हैं।

आयात में कमी की जाए : हमारी धरती में बहुमूल्य खनिज भंडारों को देखते हुए, कोई कारण नहीं है कि भारत को कोई प्राकृतिक संसाधन आयात करना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत तीन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों- कच्चा तेल, सोना और तांबा के मामले में आयात पर निर्भर है, जिसकी वजह से देश का व्यापार घाटा पिछले वित्त वर्ष में 238 अरब डालर तक पहुंच गया था। ये तीनों प्रमुख प्राकृतिक संसाधन कुल संसाधनों के आयात का 60 प्रतिशत हिस्सा हैं। हम अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 90 प्रतिशत, तांबे की आवश्यकता का 95 प्रतिशत और सोने की आवश्यकता का 90 प्रतिशत से अधिक आयात करते हैं। साथ ही, बड़ी मात्रा में कोयला और बाक्साइट का भी आयात करते हैं, जबकि हमारे यहां कोयला और बाक्साइट बड़ी मात्रा में हैं।

लेकिन यह स्थिति केवल चार नीतिगत उपायों से पूरी तरह से बदल सकती है। पहला खनन का नया तरीका, पर्यावरण एवं अन्य मंजूरियों का सेल्फ सर्टिफिकेशन, मौजूदा खनिज परिसंपत्तियों का पुनरुद्धार और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच समान अवसर। सबसे पहले, खनन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। दुनियाभर में खनन का काम छोटी खनन कंपनियां करती हैं, जो बड़ी कंपनियों की तुलना में स्टार्टअप की तरह अधिक काम करती हैं। वे खनन के हाई रिस्क को उठाती हैं। जिसमें 10 में से नौ बार खनिज की खोज में मायूसी हाथ लगती है। लेकिन दुनियाभर में एक खोज से ये कंपनियां पैसा कमाकर अपने खनिज खोज के काम को आगे बढ़ाती रहती हैं।

भारत में खनिजों की खोज की वर्तमान नीति व्यवस्था में खनिज ब्लाक्स की नीलामी की जाती है। लेकिन यह प्रणाली काम नहीं करती। आज भी भारत में मोटे तौर पर सरकार ही आधारभूत खनन का काम करती है और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास पूरे देश में बेहतर तरीके से खनन के लिए संसाधनों का अभाव है। ऐसे में हमें अपने युवा उद्यमियों पर भरोसा करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि खनिज की खोज से फीस हटा दे। खनिज की खोज पर सरकार, किसी भी स्थिति में रायल्टी और टैक्स तो वसूलेगी ही, जिससे उसकी कमाई होगी।

प्राकृतिक संसाधनों के घरेलू उत्पादन को मिलनी चाहिए प्राथमिकता। फाइल

दुनिया के अधिकांश हिस्सों में खनिज की खोज से खनन तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन भारत में यह समय विश्व के अन्य देशों की तुलना में कहीं बहुत अधिक लगता है, क्योंकि इसमें पर्यावरण से लेकर दूसरी कई मंजूरियां शामिल होती हैं और उन्हें देने में लंबा समय लगता है। इस तरह की जटिल प्रणाली के बजाय हमें सेल्फ सर्टिफिकेशन की ओर बढ़ना चाहिए। सरकार मानदंडों और मानकों की एक नियम पुस्तिका बना सकती है जिनका पालन करना अनिवार्य है। उद्यमियों को सेल्फ सर्टिफिकेशन करना होगा। बाद में एक आडिट प्रक्रिया के माध्यम से सरकार किसी भी चूक के लिए कंपनियों को जवाबदेह ठहरा सकती है। जैसा कि सरकार आयकर जैसे कुछ क्षेत्रों में कर रही है। आयकर भी लोग स्वयं जमा कराते हैं और बाद में सरकार उसकी जांच करती है। सरकार इस प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रही है।

देश को प्राकृतिक संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के इन चारों उपायों के लिए किसी भी तरह के सरकारी बजट की आवश्यकता नहीं है। बल्कि यह तो सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी ही करेंगे। साथ ही, इन उपायों से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और लाखों नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। सबसे बढ़कर आयात बिल की वजह से जो नुकसान देश को हो रहा है, उससे बचकर हम देश को 2047 तक विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे।